

कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर

Email:-dlo.jlr@rajasthan.gov.in

क्रमांक / सान्याअवि / 2022 / 625

पता:- नर्मदा कॉलोनी, सामतीपुरा रोड़, जालोर

दिनांक :—05.01.2022

खुली निविदा सूचना (दर संविदा)

निविदा संख्या—02

जिला कार्यालय के अधीनस्थ संचालित राजकीय छात्रावासों में खेलकूद सामग्री यथा क्रिकेट किट, बैडमिंटन सामग्री, फुटबॉल, बॉलीबॉल सामग्री, इन्डोर गेम कैरम, पजल्स, चैस आदि क्य हेतु जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत / बोनाफाइड विर्निमाता / पंजीकृत डीलर एवं प्राधिकृत राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड से पंजीकृत फर्मों से मौहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.सं.	अनुमानि त लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	अमानत राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत)	निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारम्भ तिथि व समय	निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्राप्ति की अंतिम दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक व समय
1	2.75	500 / रुपये	वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 2(1)वित्त / जीएण्डट १-एसपीएफसी / 20 17 दिनांक 23.12. 2020 के अनुसार घोषणा पत्र	05.01.2022 को प्रातः 9.30 बजे से	11.01.2022 को प्रातः 10 बजे तक	12.01.2022 को दोपहर 11.00 बजे तक	12.01.2022 को अपराह्न 01.00 बजे

निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्तें कार्यालय के नोटिस बोर्ड, विभागीय बेबसाइट

www.sje.rajasthan.gov.in एवं SPPP portal पर उपलब्ध हैं।

सहायक निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जालोर

क्रमांक / सान्याअवि / 2022 / 626—631

दिनांक :—05.01.2022

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में डीपीआर दरों पर प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
4. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को विभागीय बेबसाइट पर निविदा अपलोड करने हेतु।
5.
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली

सहायक निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जालोर

कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर

Email:-dlo.jlr@rajasthan.gov.in

पता:- नर्मदा कॉलोनी, सामतीपुरा रोड़, जालोर

क्रमांक / सान्याअवि / 2022 / 632

दिनांक :—05.01.2022

खुली निविदा सूचना (दर संविदा)

निविदा संख्या—02

जिला कार्यालय के अधीनस्थ संचालित राजकीय छात्रावासों में खेलकूद सामग्री यथा किकेट किट, बैडमिंटन सामग्री, फुटबॉल, बॉलीबॉल सामग्री, इन्डोर गेम कैरम, पजल्स, चैस आदि क्य हेतु जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत / बोनाफाइड विर्तिमाता / पंजीकृत डीलर एवं प्राधिकृत राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड से पंजीकृत फर्मों से मौहरबन्द निविदायें आमत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	अमानत राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत)	निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारम्भ तिथि व समय	निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्राप्ति की अंतिम दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक व समय
1	2.75	500 / रुपये	वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 2(1)वित्त / जीएण्डटी—एस पीएफसी / 2017 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार घोषणा पत्र	05.01.2022 को प्रातः 9.30 बजे से	11.01.2022 को प्रातः 10 बजे तक	12.01.2022 को दोपहर 11.00 बजे तक	12.01.2022 को अपराह्न 1.00 बजे

1. निविदा शुल्क एवं निविदा प्रतिभूति घोषणा के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी।
3. निविदा आवेदक फर्म जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिये।
4. निविदा प्रपत्र कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कलैकटट परिसर, जालोर से किसी भी कार्य दिवस में ई—ग्रास पर मद 0075—00—800—52—01 में जरिए चालान निर्धारित निविदा शुल्क राशि 500 /— रुपये जमा कराकर दिनांक 11.01.2022 को प्रातः 10 बजे तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं या बेबसाईट <http://www.sje.rajasthan.gov.in> से या SPPP WEBPORTAL से भी डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा उन्हीं निविदादाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा निर्धारित निविदा शुल्क 500 /— रुपये की राशि ई—ग्रास पर मद 0075—00—800—52—01 में जरिए चालान, एवं निविदा प्रतिभूति राशि सम्बन्धी घोषणा पत्र (50 रुपये के स्टाम्प पर अभिलिखित हो) दिनांक 12.01.2022 को दोपहर 11.00 बजे तक कार्यालय में जमा करा दिये गये हो। निविदा निर्धारित दिनांक 12.01.2022 करे अपराह्न 1.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी।

सहायक निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

जालोर

दिनांक :—05.01.2022

क्रमांक / सान्याअवि / 2022 / 633—637

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में डीपीआर दरों पर प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
4. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को विभागीय बेबसाईट पर निविदा अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / रक्षित पत्रावली।

Subhash

सहायक निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जालोर

कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर

Email:-dlo.jlr@rajasthan.gov.in

पता:- नर्मदा कॉलोनी, सामतीपुरा रोड़, जालोर

क्रमांक / सान्याअवि / 2022 / 638

दिनांक :—05.01.2022

तकनीकी निविदा (स्टेज- I) (लिफाफा- I)

विषय :— राजकीय छात्रावासों में खेल सामग्री सप्लाई करने हेतु दर संविदा

1. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता :—
.....
.....
2. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाइल नम्बर :—
3. निविदादाता का ई-मेल एड्रेस :—
4. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक :— /2021–22 दिनांक
5. हम सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या/2021–22 दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
6. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण :—

क्र.सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हॉ अथवा नहीं	वैधता एवं संलग्न पृष्ठ संख्या
1	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 500/- जमा के चालान की प्रति		
3	सूचना में अंकित अमानत राशि जमा कराने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी /2017 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार घोषणा पत्र		
4	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)		
5	आयकर (पैन नम्बर)		
6	बोलीदाता के किसी भी विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट/डिबार न किये जाने संबंधी वचनबद्धता पत्र स्केन कर अपलोड करें।		

7. निविदा शुल्क जरिए चालान एवं अमानत राशि जरिए चालान जमा करवाकर कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से जमा करावें। कृपया इसका विशेष ध्यान रखें।

हस्ताक्षर निविदादाता

कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर

Email:-dlo.jlr@rajasthan.gov.in

पता:- नर्मदा कॉलोनी, सामतीपुरा रोड़, जालोर

क्रमांक / सान्याअवि / 2022 / 639

दिनांक :—05.01.2022

वित्तीय निविदा (लिफाफा—2)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता एवं मोबाइल नम्बर.....
2. निविदा शुल्क की राशि.....चालान संख्या..... एवं दिनांक.....द्वारा जमा करवा दी गई है।
3. प्रतिभूति राशि सम्बन्धी घोषणा पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संलग्न है।
4. विभाग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या..... दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों के बाध्य होना स्वीकार करते हैं(इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं)
5. निम्नलिखित मदों की सप्लाई के लिये दरें निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गई है।
6. सामग्री विवरण :-

क्र. सं.	सामान का विवरण	नग प्रति छात्रा वास	कुल छात्रावासों की संख्या	कुल मात्रा	दर प्रति ईकाई	कुल राशि (संख्या X दर प्रति इकाई)	जी.एस.टी. कर	कुल योग
किंकेट सामग्री :-								
1	फ्रिकेट बैट	02	08	16				
2	विकेट सेट	02	08	16				
3	गेंद टेनिस	05	08	40				
बैंडमिटन सामग्री :-								
4	रैकिट	04	11	44				
5	नेट	01	11	11				
6	कॉक डिब्बा	02	11	22				
बॉलीवाल सामग्री :-								
7	बॉलीवाल	01	11	11				
8	नेट	1	11	11				
अन्य सामग्री :-								
9	फुटबॉल	01	11	11				
10	कैरस बोर्ड बडासाइज	01	11	11				
11	रस्सी कूदने वाली (3 एकल, 3 लम्बी)	06	11	66				
12	रिंग	06	03	18				
13	शतरंज	02	11	22				
कुल योग								

7. सामान की मात्रा आवश्यकता के अनुरूप घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
8. सफल संवेदक फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 10 दिवस में सम्बन्धित छात्रावासों पर एफओआर सामान की सुपुर्दगी कर दी जानी आवश्यक है।
9. उपर उद्धृत की गई दरें 31.03.2022 तक के लिये विधिमान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
10. विनिर्माता / डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

जिला जालोर के अधीन संचालित राजकीय छात्रावासों की सूची :-

क्र.सं.	नाम छात्रावास	छात्रावास का पूर्ण पता	स्थीकृत प्रवेश संख्या
1	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, आहोर	नर्सरी के पास जोधपुर रोड़, आहोर	50
2	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, बागरा	132 kv GSS के पास, बागरा	25
3	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, भाद्राजून ढाणी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास भाद्राजून रोड़	25
4	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, जालोर-II	FCI गोदाम के पास जालोर	50
5	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, सांचौर	नर्मदा कॉलोनी हवाई पट्टी के पास सांचौर	60
6	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, सायला-I	न्यू बस स्टेण्ड के पीछे सायला	35
7	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, सायला-II	न्यू बस स्टेण्ड के पीछे सायला	40
8	राजकीय देवनारायण छात्रावास, सांचौर	बी ढाणी अरणाय रोड़ सांचौर	50
9	राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास, जालोर	दूरदर्शन रिले केन्द्र के सामने जालोर	50
10	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास , जालोर	132 kv GSS के पास, आहोर रोड़ जालोर	100
11	राजकीय सावित्रि बाई फुले छात्रावास , जालोर	दूरदर्शन रिले केन्द्र के सामने जालोर	50

निविदा की सामान्य शर्तें:-

1. निर्धारित प्रपत्र बेबसाईट <http://www.sje.rajasthan.gov.in> या SPPP WEBPORTAL से या कार्यालय समय में कार्यालय से दिनांक 11.01.2022 समय प्रातः 10 बजे तक निविदा शुल्क जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। भरी हुई निविदा दिनांक 12.01.2022 को दोपहर 11.00 बजे तक कार्यालय में जमा की जाकर उसी दिन 01.00 बजे क्य समिति एवं उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. यदि किसी कारण वश उस दिन का अवकाश रहता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर खोली जावेगी।
3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क जरिए चालान सम्बन्धित मद में जमा करवाकर व धरोहर राशि सम्बन्धी घोषणा पत्र निर्धारित दिनोंके को कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदाएं स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
5. निविदा द्वारा अनुमोदित की गई अनुबन्ध की दिनांक 31.03.2022 तक के लिये विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
6. निविदा के साथ वेट/बिकी कर पंजीयन एवं नवीनतम वेट/बिकी कर दिनांक 30.12.2021 तक चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. विनिर्माता/डीलर आदि को घोषणा पत्र(एस.आर.-11) संलग्न करनी होगी।
8. विभाग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता है। इसके सहमति स्वरूप निविदा के सभी पृष्ठों व उल्लेखित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण पत्र में सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
9. अपूर्ण अथवा अहस्ताक्षरित निविदा अमान्य होगी।
10. निविदादाता जीएसटी अधिनियम 2017 के अधीन पंजीकृत व्यवसायी होना चाहिए एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करनी होगी।
11. दरें सम्बन्धित छात्रावासों तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी अनुषंगिक प्रभारी (सामग्रीलागत, पैकिंग, परिवहन, लॉडिंग/अनलोडिंग, नाप, तोल, संस्थापन तथा सभी प्रकार के कर व शुल्क,जीएसटी के अतिरिक्त) को शामिल करना होगा।
12. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिये यह समझा जाएगा कि उसने प्रदान किये जाने वाले माल की शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक, एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि इन शर्तों विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह होता वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
13. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े(सब लैट) पर नहीं देगा।
14. विनिर्देश-(1)प्रयुक्त की गई वस्तुएं निविदा के साथ प्रस्तुत नमूना के पूर्णतया अनुरूप होगी एवं जिन वस्तुओं का नमूना उपलब्ध नहीं है उन वस्तुओं बृशर साथ में देना होगा। (2)वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित न हो, वहाँ अतिउत्तम गुणवता, एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा।
15. निविदादाताओं या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
16. (1)सुपुर्दगी अवधि:-निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाये सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नागौर द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर आदेशानुसार कार्य स्थल पर सामग्री की आपूर्ति करेगा।

17. (2)यदि कार्यकारी संस्था निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में सामग्री आपूर्ति करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
18. विलम्ब से सुपुर्दगी करने पर जी.एफ.एण्ड.आर. के नियमानुसार राशि की कटौती की जावेगी।
19. आपूर्तिकर्ता को आदेशित सामग्री का सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जालोर की मांग के अनुसार कार्य करना होगा। इससे भिन्न आईटम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. सामग्री की आपूर्ति के लिये आदेश सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जालोर द्वारा आवश्यकतानुसार दिया जायेगा।
21. सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जालोर जारी कर्य आदेश के कम में आपूर्ति की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि तथा कर्य समिति के सत्यापन पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जालोर द्वारा एक प्रति कार्यालय उपयोग के लिये तथा दूसरी प्रति को प्रमाणित कर बिल के साथ भेजी जावेगी।
22. धरोहर राशि—(क)निविदा के साथ अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत धरोहर राशि प्रस्तुत की जावेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जालोर के पक्ष में बैंकर चैक के रूप में जमा करानी होगी। (ख)धरोहर राशि का प्रतिदाय—असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटायी जाएगी। (ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपकरणों को कोई बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
23. धरोहर राशि का सम्परहण—बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में सम्परहण कर लिया जाएगा: (1)जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है,या उसमें रूपान्तरण करता है। (2)जब विनिदादाता विर्णिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को,यदि कोई हो,निष्पादित नहीं करता है। (3)जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है। (4)जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारंभ करने में असफल रहता है।
24. (1)करार एवं प्रतिभूति निष्केप—(1)सफल निविदादाताओं को आदेश के प्राप्त होने से 3 दिन की अवधि के भीतर एक करार पत्र रूपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिन कार्यों के लिये निविदायें स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। तथा एसएसआई यूनिट के अन्तर्गत पार्ट—2 में पंजीकृत फर्मों को निविदा के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिनकी निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गयी है, 3 दिन के भीतर जमा करवायी जायेगी। (2)निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि से कम की नहीं होगी। (3)प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। (4)प्रतिभूति राशि बैंकर चैक के रूप में ही जमा करवानी होगी।
(2)प्रतिभूति निष्केप का सम्परहण—प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में सम्परहण किया जा सकता—(क)जब संविदा के किन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने का केताधिकारी को पूर्ण होगा।(ग)प्रतिभूति निष्केप का सम्परहण करने के मामले में 7 दिवस का नोटिस दिया जायेगा।तथा प्रतिभूति राशि सम्परहण कर फर्म को विसर्जित कर दिया जावेगा।इस संबंध में केताधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
25. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल जीएसटी राशि को अलग दर्शाया जाकर बिल प्रस्तुत करना होगा संबंधित विभाग में जीएसटी राशि जमा करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा।
26. भुगतान बिलों से नियमानुसार आयकर/जीएसटी की कटौतियां की जावेगी।
27. कर्य समिति द्वारा स्वीकार की गई निविदा पर द्वारा 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करने का प्रावधान

28. सामग्री सम्बन्धित छात्रावासों में सुपुर्द कर पावती प्राप्त करनी है।
29. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थागित किया जाना आवश्यक हो किसी पक्षकार जिला जालोर में स्थित न्यायालयों में ही की जावेगी।
30. निविदा संबंधी समस्त अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित होंगे जिनका निर्णय अंतिम एवं सार्वमान्य होगा।
31. अन्य समस्त शर्तों राज्य सरकार के उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में उल्लेखित क्रय नियम एवं समय—समय पर जारी दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।
32. सक्षम स्तर से स्वीकृति मिलने पर ही कार्यादेश दिये जावेगे।
33. निविदादाता द्वारा विहित समय पर सामग्री आपूर्ति न करने की स्थिति में निविदा फर्म से ठीक बाद वाली निविदा फर्म को सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है।
34. वित्तीय निविदा खोलने से पहले निविदादाताओं से अलग से प्राप्त लिफाफे खोले जायेंगे जिसमें आयकर विवरणी, जीएसटी पंजीयन फर्म रजिस्ट्रेशन, फर्म के स्वामी का पैन कार्ड इत्यादि की छायांप्रति संलग्न होनी अनिवार्य है। बिना इसके संबंधित निविदादाता के वित्तीय निविदा न ही खोली जावेगी।
35. उपापन समिति संबंधित फर्मों के आपूर्ति स्थान पर जाकर माल की किस्म की जाँच करेगी एवं मानक स्तर से कम पाये जाने पर निविदा निरस्त कर इसके ठीक नीचे की दरों वाली फर्म को दी जा सकती है।

मैंने/हमने उक्त शर्तों को पढ़कर समझ लिया है एवं इनसे पूर्णतयः सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम
पता
मोबाईल नम्बर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषण करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरण/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेण्ट हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समर्पित कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest
Any person participation in a procurement process shall.

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not include in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participation in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

i.A. Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

- a. have controlling partners/shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties. that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity a engineer-in-charge/ consultant for the contract.

**Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to.....for procurement of.....in response to their Notice Inviting Bids No.....Dated.....I/we hereby declare under Section7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement of misrepresentations as to my/our professional conduct or the making of false statements or representations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
bidder

Signature of

Place:

Name:
Designation:
Address:

ANNEXURE C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is.....

The designation and address of the Second Appellate Authority is.....

(1) Filling an appeal- If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act of the Rule or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Documents within a period of then days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or gorunds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it off within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the other passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be , may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) From of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts state in the appeal and proof or payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filling Appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon Filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall
 - i. hear all the parties to appeal present before him; and
 - ii. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspections of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM NO. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the rajasthan transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- i. Name of the appellant:
- ii. Official address, if any:
- iii. Residential address:

2. Name and address of the respondents(s):

- i.
- ii.
- iii.

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with appeal:

6. Grounds of appeal:
.....(Supported by an affidavit)

7.

Place.....

Date.....

Appellant's Signature

Annexure D: Additional conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit prices shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- III. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurements or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier

fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award

(In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in the order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.